पश्चिम की त्रासदी: यूक्रेन की कुर्बानी और नियम-आधारित व्यवस्था

ग्लोबल डेमोक्रेसी और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए यूक्रेन क्यों ज़रूरी है

CEED
JUN 15, 2026

यूक्रेन एक टूटी-फूटी लेकिन मज़बूत ढाल की तरह खड़ा है, जबकि न्याय के टूटे हुए तराजू नियमों पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर के कमज़ोर होने की निशानी हैं।

रूस के हमले वाले युद्ध का नतीजा पश्चिम की उलझन की वजह से है, जिसने लड़ाई में यूक्रेन के बचाव का साथ दिया और रूस से पैदा होने वाले खतरे के हिसाब से अपने जवाब को बढ़ाने से मना कर दिया। नियमों पर आधारित व्यवस्था खतरे में है, और यूक्रेन अपने बचाव में अकेला खड़ा है।

2024 की पतझड़ में, US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ठीक पहले, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने उस समय के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन के लिए अपना विक्ट्री प्लान दिखाया था। अब, ठीक एक साल बाद, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को एक अल्टीमेटम दिया है, जिसमें कीव से यूक्रेन के रूस के सामने सरेंडर करने के लिए 28-पॉइंट फ्रेमवर्क को मानने की मांग की गई है।

रूस लगभग बारह साल के क्रूर युद्ध और नरसंहार के बाद भी यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं कर पाया है, लेकिन ऑफिस में एक साल से भी कम समय में, ट्रंप एक नकली 'शांति' डील के ज़रिए यूक्रेन को हार मानने के लिए मजबूर करने के करीब हैं। घटनाओं का यह नाटकीय मोड़ ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद से ग्लोबल सिक्योरिटी सिस्टम में आए बड़े बदलाव को दिखाता है।

अमेरिकी दबाव के साथ यूक्रेन – और यूरोप – से क्रेमलिन की मांगों का समर्थन करके, US एडमिनिस्ट्रेशन मॉस्को को यूक्रेन के खिलाफ 'शांति' को हथियार बनाने में मदद कर रहा है। असल में, ट्रंप का प्रपोज़ल रूस के बिना उकसावे वाले, गैर-कानूनी हमले को सही ठहराता है। हमलावर को इनाम देकर और पीड़ित को सज़ा देकर – अपनी आज़ादी को सीमित करके, अपने लोगों को

कब्ज़े में डालकर और सच्ची सुरक्षा, न्याय और मुआवज़े से इनकार करके – US सरकार दुनिया को लिबरल, नियमों पर आधारित व्यवस्था के खत्म होने की कगार पर धकेल रही है।

आज, लिबरल, नियमों पर आधारित व्यवस्था की किस्मत यूक्रेन के युद्ध के मैदानों पर उतनी ही तय हो रही है जितनी पश्चिमी देशों के रुख से। जबकि यूक्रेन के लोगों ने कड़ी लड़ाई और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के बावजूद नियमों पर आधारित व्यवस्था की अगली लाइन संभाली है, पश्चिमी देश बिना लड़े इसे छोड़ सकते हैं। रूस के युद्ध का कोई भी समझौता, जो इंटरनेशनल कानून की खुलेआम अनदेखी पर आधारित हो, एक विनाशकारी गेंद बन जाएगा, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सिस्टम के बचे-खुचे दिखावे को खत्म कर देगा।

रूस को रोकने में पश्चिमी देशों की नाकामी सालों से आज़ादी की 'नई व्यवस्था' का रास्ता बना रही है

ट्रंप की 28-पॉइंट की लिस्ट इस बात की निशानी है कि पश्चिम दुनिया के मामलों में अपनी लीडरशिप तेज़ी से बढ़ती तानाशाही ताकतों के हाथों खो रहा है।

पिछले आठ दशकों से, पश्चिम का ग्लोबल असर लिबरल नियमों पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर की ताकत और अपील पर टिका रहा है, जिसने इंसानों को दशकों तक पहले कभी नहीं देखी गई सुरक्षा, आज़ादी का दुनिया भर में फैलाव और इंसानी इज्ज़त की सुरक्षा और दुनिया भर में बढ़ती खुशहाली का मज़ा लेने दिया। अब इसे हमारी आँखों के सामने खत्म किया जा रहा है।

पश्चिम की यह दुखद घटना मिलिट्री हार का नतीजा नहीं है, बल्कि उन लंबी समझौता वाली पॉलिसी का अंदरूनी नतीजा है, जिन्होंने तानाशाही सरकारों को हिम्मत दी है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे बुरे लोगों ने पश्चिमी देशों में नियमों पर आधारित ऑर्डर को बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाने की पॉलिटिकल इच्छाशक्ति की कमी का फ़ायदा उठाया है।

रूस के प्रति पश्चिमी पॉलिसी को हर तरह से नुकसान हुआ है। पश्चिमी सरकारों ने पुतिन के बदला लेने वाले शासन को बढ़ावा देने के लिए दिल खोलकर पैसे दिए हैं, जबकि उन्होंने बढ़ते तानाशाही, मिलिट्रीकरण और रूस की आक्रामक विदेश नीति के साफ़ खतरे को भी देखा है।

रूस के साथ करीबी रिश्ते बनाने की कोशिश में, पश्चिम ने अपने सुरक्षा हितों की अनदेखी की है। रूस के इंटरनेशनल कानून तोड़ने का इनाम उसे 'रीसेट' और ग्लोबल इकॉनमी में ज़्यादा इंटीग्रेशन के तौर पर मिला है। असल में, पश्चिम रूस के बदला लेने वाले एजेंडा को पूरा करने के लिए अपने बताए गए उसूलों को फिर से बदल रहा है। रूस पश्चिम को न सिर्फ़ गैस और तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, बल्कि ऊंचे लेवल के राजनीतिक और बिज़नेस संस्थानों में भ्रष्टाचार, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तोड़ना, प्रोपेगैंडा, अपने असर का नेटवर्क, ऑर्गनाइज़्ड क्राइम और इंटेलिजेंस एजेंट भी एक्सपोर्ट कर रहा है।

2014 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की जंग शुरू की, तो पश्चिमी बयानबाज़ी बदल गई, लेकिन उसकी पॉलिसी का मतलब – मॉस्को को खुश करना, जो तीन बातों पर आधारित था: इंटरनेशनल कानून को बनाए रखने से बचना, यूक्रेन के हितों को कुर्बान करना और हमेशा की तरह बिज़नेस जारी रखना – नहीं बदला।

रूस के गैर-कानूनी हमले को 2022 तक कोई पहचान नहीं मिली। 2014 में मॉस्को पर लगाए गए सिर्फ़ सिंबॉलिक बैन, इंटरनेशनल कानून और यूरोप के सिक्योरिटी ऑर्डर पर रूस के खुलेआम हमले की गंभीरता को नहीं दिखाते थे। यूक्रेन पर असल

में मिलिट्री बैन 'रूस को भड़काने के लिए नहीं' लगाया गया था; असल में, यह यूक्रेन को कमज़ोर और दब्बू बनाए रखने के लिए था। किसी भी यूक्रेनी की हत्या के लिए किसी भी रूसी को इंटरनेशनल सज़ा नहीं मिली है। बर्बाद हुई जान या प्रॉपर्टी के लिए कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया है। रूसी इकॉनमी में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट जारी रहे हैं। रूसी एनर्जी पर ज़रूरी डिपेंडेंसी बढ़ाते हुए यूरोपियन सिक्योरिटी के हितों को नज़रअंदाज़ किया गया – दूसरी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन स्ट्रेटेजिक करप्शन की बदनाम निशानी थी। मॉस्को को खुश करने से रूस में चल रहे करप्ट बिज़नेस और क्रेमलिन शैडो फाइनेंसिंग से फ़ायदा उठाने वाले पॉलिटिकल एक्टर्स को फ़ायदा हुआ है, जबकि कुल मिलाकर वेस्टर्न सोसाइटी कमज़ोर हुई हैं।

2014 में, यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले के जवाब में, US कांग्रेस ने **यूक्रेन फ्रीडम सपोर्ट एक्ट** अपनाया। इस कानून ने अमेरिका के पॉलिसी मकसद को बताया कि रूस को यूक्रेन पर और हमला करने से रोका जाए और आर्थिक पाबंदियों, डिप्लोमेसी, यूक्रेन के लोगों की मदद और मिलिट्री क्षमता देकर यूक्रेन को अपनी सॉवरेनिटी और इलाके की एकता वापस दिलाने में मदद की जाए। फिर भी, इस मकसद के मुताबिक कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत कम कोशिशों की वजह से, रूस का हमला दबाया नहीं जा सका। इसके उलट, पश्चिमी देशों के फैसले न लेने और कुछ न करने की वजह से रूस को दुनिया के सामने यूक्रेन के लोगों के खिलाफ नरसंहार की अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाने का हौसला मिला।

फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस की लड़ाई का बहुत ज़्यादा बढ़ना पश्चिम में कई लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी थी, जिससे पश्चिमी रूस की पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव आया। रूस के खिलाफ़ धीरे-धीरे और कड़े कदम उठाए गए और यूक्रेन की रक्षा कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए पश्चिमी देशों का सपोर्ट ज़रूरी हो गया। जो नहीं बदला है, वह है रूस की लड़ाई पर पश्चिमी देशों के जवाब का असली मकसद – यूक्रेन की कीमत पर मॉस्को को खुश करना होगा। रूस को हराने में यूक्रेन की मदद करने का वादा करने के बजाय, पश्चिम ने यूक्रेन को 'सबसे अच्छी बातचीत की स्थिति' में रखने की आड़ में उसे खुश करने का तरीका चुना, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें कीव की मॉस्को को 'अपनी मर्ज़ी से' दी गई रियायतें शामिल थीं। पश्चिम ने जिस एकमात्र रेड लाइन पर खुद को कमिट किया है, वह है यूक्रेन को एक सॉवरेन देश के तौर पर बनाए रखना, भले ही सॉवरेनिटी सीमित हो।

ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाली, नियमों पर आधारित व्यवस्था – जिसे उनसे पहले पश्चिमी नेताओं की कई पीढ़ियों ने बड़ी मेहनत से बनाया था – खुद को खत्म करने की स्थिति में चली गई। रूस के युद्ध के प्रति ट्रंप का नकली शांति वाला तरीका यूक्रेन को विरोध बंद करने और मॉस्को की गैर-कानूनी मांगों को 'अपनी मर्ज़ी से' मानने के लिए मजबूर करना रहा है। अगर ट्रंप के उलटे-सीधे विचार चलते रहे, तो दुनिया खुद को युद्ध अपराधी पुतिन को शांतिदूत के तौर पर स्वीकार करते हुए पा सकती है, जो खुद ट्रंप की तरह नोबेल प्राइज़ के लायक है।

रूस यूक्रेन को इसलिए बर्बाद कर रहा है क्योंकि **यूक्रेन को कम सपोर्ट मिल रहा है, जबकि रूस को ज़्यादा सुरक्षा मिल रही है**। रूस के युद्ध पर पश्चिमी देशों का रिस्पॉन्स जितने लंबे समय तक नियमों पर आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी चीज़ों के हिसाब से नहीं रहेगा, हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी व्यवस्था के खत्म होने के उतने ही करीब पहुँचते जाएँगे।

अगर हमें रूस के हमले को रोकना है, तो पश्चिमी देशों की पॉलिसी के सेंटर में दो बड़ी कमियाँ हैं जिन्हें ठीक करना होगा: मॉस्को की बदला लेने की ग्लोबल इच्छाओं को कम समझना और यूक्रेन में रूस के नरसंहार के मकसद को मानने से इनकार करना।

रूस वैश्विक शांति के लिए मुख्य खतरा है

ग्लोबल सुपरपावर का दर्जा फिर से पाने की रूस की बदला लेने की चाहत को खतरनाक तरीके से कम करके आंका गया है।

पश्चिम का मानना था कि रूस के आक्रामक प्लान को यूक्रेन या पुराने सोवियत इलाके में ही रोका जा सकता है, और इससे पश्चिमी सुरक्षा और आर्थिक हितों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि NATO को रूस का 2021 **का अल्टीमेटम** (यूक्रेन को नहीं!) भी पश्चिमी देशों के घमंडी अजेय रवैये को नहीं हिला पाया।

पश्चिम इस गलत सोच में बहक गया था कि उसकी ज़्यादा GDP उसे किसी भी खतरे से बचाती है, और उसने रूस की सोची-समझी रणनीति का विरोध करने की अपने समाज की क्षमता से जुड़ी गंभीर समस्याओं को नज़रअंदाज़ कर दिया, ताकि पश्चिमी दबदबे वाले इंटरनेशनल सिस्टम को खत्म किया जा सके। रूस ने आर्थिक मुकाबले में अपनी कमियों को बुरे कामों से मिले फ़ायदों से बदल दिया: विदेशों में क्रूर हिंसा का इस्तेमाल करना; एनर्जी सप्लाई को हथियार बनाना; दूसरे देशों के ऊंचे राजनीतिक और बिज़नेस संस्थानों को भ्रष्ट करना; सरकार के चलाए जा रहे प्रोपेगैंडा, अपने असर के नेटवर्क और बांटने वाले राजनीतिक लोगों के समर्थन से दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को तोड़ना; संगठित अपराध का फ़ायदा उठाकर अपने टारगेट को कमज़ोर करना; और खुफिया एजेंटों की घुसपैठ कराना।

जब पश्चिम पुतिन के रूस को एक सोच से धुले हुए, तानाशाही और मिलिटराइज़्ड समाज में बदलने को नज़रअंदाज़ करता रहा, तब मॉस्को चुपचाप पश्चिम को अस्थिर करने के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था और एक 'नए वर्ल्ड ऑर्डर' की शुरुआत करने के लिए बीजिंग के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहा था। चीन-रूस गठबंधन ने एक पक्का पश्चिम-विरोधी ग्रुप बनाया जो इंटरनेशनल रिश्तों की दुनिया को नया आकार दे रहा है। इस दुश्मन धुरी के सपोर्ट से रूस को इतना भरोसा हो गया कि उसने पश्चिम के खिलाफ हाइब्रिड वॉर शुरू कर दिया, जिसमें NATO के सदस्य देशों के इलाके में आतंकवाद और तोड़-फोड़ के कामों को ऑर्गनाइज़ करना, फाइनेंस करना और डायरेक्ट करना शामिल था। NATO की रोकथाम अब बिना सवाल के नहीं है।

ट्रंप के 28 पॉइंट्स ने उन फायदों पर ज़ोर दिया जो रूस ने यूक्रेन में किसी भी बड़ी मिलिट्री कामयाबी का दावा करने में नाकाम रहने के बावजूद ग्लोबल पावर पाने की अपनी कोशिश में हासिल किए। युद्ध अपराधियों द्वारा कब्ज़ा किए गए और दुनिया की शांति के लिए खतरा बने एक गैर-कानूनी देश के तौर पर देखे जाने के बजाय, रूस को इंटरनेशनल रिश्तों में खास तवज्जो दी जाती है, जिससे वह इंटरनेशनल कानून से ऊपर काम कर सकता है और न सिर्फ अपने हमले के शिकार पर बल्कि अमेरिका के सहयोगियों पर भी अपनी मर्ज़ी चला सकता है, जिसमें वह डिफेंसिव मिलिट्री अलायंस भी शामिल है जिसे अमेरिका लीड करता है।

ट्रंप का रूस को ऊपर उठाना उनके लंबे समय से चले आ रहे पब्लिक स्टैंड को दिखाता है। यूक्रेन के सरेंडर के लिए प्रस्तावित फ्रेमवर्क की डिटेल्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं है: ग्लोबल मामलों के बारे में उनके नज़रिए से, बड़ी ताकत को उसके हमले के लिए युद्ध की लूट से इनाम दिया जाना चाहिए, जबकि एक छोटे देश को उसके विरोध के लिए अपमानजनक रियायतों से सज़ा दी जानी चाहिए। यह उन देशों के लिए एक बड़ी चेतावनी होनी चाहिए जो ट्रंप के अपने आक्रामक दावों के निशाने पर हैं। ट्रंप को खुश करना उतना ही असरदार होगा जितना पुतिन को खुश करना।

यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर करना ट्रंप की उस पॉलिसी को दिखाता है जिसमें वह अमेरिका की आज़ाद दुनिया के लीडर के तौर पर लंबे समय से चली आ रही भूमिका को छोड़ना चाहते हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेशन आक्रामक फॉरेन पॉलिसी पर चल रहा है और अपने देश में डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर रहा है। ट्रंप का 'ग्रेट अमेरिका' का विज़न तेज़ी से वैसे ही आइडिया पर आधारित लगता है जो पुतिन के राज के उदय का आधार थे: 'ताकत ही सही है' पॉलिसी को सही ठहराने के लिए बदला लेने की भावनाओं को बढ़ावा देना।

यह बहुत लंबे समय से साफ़ है कि रूस के प्रति यूक्रेन की नाफ़रमानी, वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच एक नया पार्टनरशिप रिश्ता बनाने की ट्रंप की इच्छा के रास्ते में रुकावट रही है। जैसा कि 28 पॉइंट्स से साफ़ है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लिबरल रूल्स-बेस्ड ऑर्डर को खत्म करने जितनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है।

सबसे पहले, क्रेमलिन के साथ फिर से जुड़ने की इस नई कोशिश को 'रिवर्स-किसिंजर' पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बताकर सही ठहराया गया, जिसका मकसद मॉस्को को बीजिंग से अलग करके चीन को कमज़ोर करना था। इस गलत सोच वाली पॉलिसी का जल्द ही उन बड़े मकसदों की असलियत से सामना हुआ जो उस वर्ल्ड ऑर्डर को उलटने के लिए थे जो रूस और चीन को US के किसी भी स्ट्रेटेजिक बदलाव के लिए दिए जा सकने वाले किसी भी इंसेंटिव से कहीं ज़्यादा मज़बूती से जोड़ता है।

अब, यह तेज़ी से दिख रहा है कि नियमों पर आधारित ऑर्डर को खत्म करने के लिए ट्रंप की पुतिन के साथ मिलीभगत का मकसद दुनिया को, रूस और चीन के साथ, असर वाले इलाकों में बांटना है, जो 1944 के चौथे मॉस्को कॉन्फ्रेंस में हुए 'परसेंटेज एग्रीमेंट' की याद दिलाता है। अगर यूक्रेन ऐसे किसी समझौते का शिकार होता है, तो यूरोपियन यूनियन का वजूद अगले नतीजों में से एक हो सकता है।

पश्चिमी देशों को आखिरकार यह मानना होगा कि यूक्रेन के हितों को रूस के लिए कुर्बान करने से शांति नहीं आएगी; इससे और ज़्यादा जंग का रास्ता खुलेगा। पश्चिम न सिर्फ़ रूसी सेना की बर्बर चालों के ख़िलाफ़ लड़ने का बहुत ज़्यादा अनुभव रखने वाले एक काबिल मिलिट्री साथी को खो देगा, बल्कि मॉस्को को नियमों पर आधारित व्यवस्था को खत्म करने और दुनिया भर में और ज़्यादा हिंसा के दरवाज़े खोलने में भी मदद करेगा, जिसमें पश्चिमी देश सीधे निशाने पर होंगे।

रूस का लक्ष्य यूक्रेनियन को रूसी बनाना और यूक्रेन को रूस बनाना है

रूस को रोकने में पश्चिमी देशों की नाकामी का दूसरा बड़ा कारण यूक्रेन में रूस के क्रिमिनल कामों की असली पहचान को न मानना है। यह खत्म करने, नरसंहार, कल्चर, भाषा और इको-हत्या की लड़ाई है।

2014 से, रूस यूक्रेनी सरकार और यूक्रेनी देश दोनों को खत्म करना चाहता है। नरसंहार का यह मकसद ही रूस के यूक्रेन पर लगातार लड़ाई का मुख्य कारण है। यही वजह है कि मॉस्को की शाही लालच यूक्रेन के दक्षिण-पूर्व में और इलाका तुष्टीकरण की थाली में परोसकर पूरी नहीं हो सकती।

रूसी सरकार खुलेआम रूसवाद की इंसानियत से नफरत करने वाली सोच का समर्थन करती है और अपने लोगों को सरकार की चलाई जा रही बड़े पैमाने पर प्रोपेगैंडा मशीन के ज़रिए यूक्रेन के लोगों के खिलाफ नरसंहार करने के लिए उकसाती है।

रूस के भयानक अपराधों की एक लिस्ट यूक्रेन के लोगों को खत्म करने के लिए सरकार की सोची-समझी योजना का खुलासा करती है: आम लोगों पर रूस के हमलों का भयानक पैमाना, क्रूरता और पैटर्न; **आम लोगों और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हवाई हमले** जो पहले कभी नहीं हुए; **ड्रोन से आम लोगों का शिकार** करने की एक सिस्टमैटिक 'ह्यूमन सफारी' टैक्टिक; नेताओं, एक्टिविस्ट, पत्रकारों, धार्मिक पादरियों को जानबूझकर निशाना बनाना; सामूहिक कब्रें; **बच्चों को गैर-कानूनी तरीके** से देश से निकालना और उनकी पहचान मिटाने और उन्हें मिलिट्री की शिक्षा देने के लिए उन्हें गलत शिक्षा देना; सिस्टमैटिक भयानक हिंसा, टॉर्चर, रेप; शहरों की मिलिट्री घेराबंदी; और भी बहुत कुछ।

पश्चिमी सरकारों को यह नज़रअंदाज़ करना बंद करना होगा कि रूस जानबूझकर, सरकार के इशारे पर पॉलिसी लागू कर रहा है, जिसका मकसद यूक्रेन के लोगों को एक अलग राष्ट्रीय और जातीय ग्रुप के तौर पर खत्म करना है। यह यूक्रेन के आज़ाद देश को खत्म करने का एक तरीका है, क्योंकि यूक्रेनी देश का होना ही यूक्रेन के राज की नींव है।

पश्चिम लड़ाई से बाहर रहकर हार रहा है

रूसी नरसंहार को रोकने में यूक्रेन की मदद करने में पश्चिमी देशों की राजनीतिक हिचकिचाहट ने यूक्रेन को कभी न खत्म होने वाली तबाही के लिए मजबूर कर दिया है। जब से ट्रंप ने यूक्रेन पर अमेरिकी पॉलिसी बदली है, तबाही का पैमाना तेज़ी से बढ़ा है।

यूक्रेन को किसी तथाकथित 'पीस प्लान' की ज़रूरत नहीं है जो क्रिमिनल रूसी शासन को जवाबदेही से बचाए और मानवीय चिंताओं की आड़ में रूस को उसके युद्ध के इनाम से पुरस्कृत करे। टेबल पर केवल एक ही पीस प्लान होना चाहिए: इंटरनेशनल कानून की पूरी बहाली, जिसका उल्लंघन रूस के यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक युद्ध और यूक्रेनियन के खिलाफ उसके नरसंहार से हुआ था। इस प्लान के लिए रूस को हराना ज़रूरी है, और यह मकसद हासिल किया जा सकता है। यूक्रेन ने पहले ही साबित कर दिया है कि रूस मिट्टी के पैरों पर खड़ा एक बड़ा योद्धा है।

यूक्रेन युद्ध के मैदान में आखिरी योद्धा के रूप में खड़ा है, जो लिबरल ग्लोबल ऑर्डर को बचाने के लिए लड़ रहा है। जबकि कुछ पश्चिमी नेता मानते हैं कि यूक्रेन इस साझा मकसद की अगली लाइन में है, उनकी एकजुटता की घोषणाओं को मज़बूत राजनीतिक, आर्थिक और मिलिट्री कार्रवाई में बदलना होगा:

- यूक्रेन की सेल्फ-डिफेंस के लिए फाइनेंस करने के लिए रूस की सॉवरेन एसेट्स को ज़ब्त करना।
- रूस पर पूरी तरह से इकोनॉमिक बैन लगाना ताकि उसे जंग जारी रखने के लिए रिसोर्स से दूर रखा जा सके।
- यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार सप्लाई करना ताकि रूस की आम आबादी को टारगेट करने की कैपेसिटी को काफी हद तक कम किया जा सके।
- वॉर क्राइम और जेनोसाइड के रूसी अपराधियों पर इंटरनेशनल कोर्ट में केस चलाना ताकि यह साफ मैसेज जाए कि यूक्रेन के लोगों के लिए इंसाफ को किसी भी बातचीत में मोलभाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
- यूक्रेन की सीमा से लगे NATO मेंबर देशों को रूस के हवाई खतरों से मिलकर बचाव करने के लिए यूक्रेन के साथ कोऑपरेट करना शुरू करना चाहिए।
- यूक्रेन के आम लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने और यूक्रेन के सिविलियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूसी हमलों से होने वाली न्यूक्लियर घटना के खतरे को कम करने के लिए एक ह्यूमनिटेरियन मिलिट्री मिशन शुरू करना, जिससे पूरे यूरोप की सेफ्टी को खतरा है।
- ऐसी पॉलिसी अपनाना जो रूस के डीकोलोनाइजेशन और डी-इंपीरियलाइजेशन को सपोर्ट करती है।
- NATO सदस्यों के इलाके में आतंकवादी हमलों को ऑर्गनाइज़ करने, फंडिंग करने और डायरेक्ट करने के लिए रूस को आतंकवाद का स्पॉन्सर देश घोषित करना।
- पश्चिमी और यूक्रेनी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ की सुरक्षा के लिए यूरोपियन मिलिट्री के लोगों को तैनात करना।
- यूक्रेन की सेल्फ-डिफेंस मिलिट्री कोशिशों को मज़बूत करने के लिए तैयार लोगों का एक ग्रुप भेजना।

- यूक्रेन को NATO मेंबरशिप का ऑफर देना।

भविष्य की रक्षा करें

नियमों पर आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कमिटमेंट, एक्शन और उन मुख्य मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए ज़रूरी जोखिम उठाने की इच्छा की ज़रूरत होती है, जिन पर यह व्यवस्था आधारित है।

रूस सिर्फ़ यूक्रेन के साथ युद्ध में नहीं है; यह इंसानियत के साथ युद्ध में है। यूक्रेन की रेड लाइन्स इंटरनेशनल नियमों पर आधारित व्यवस्था की सीमाएं हैं। यूक्रेन को 'अपनी मर्ज़ी से' सीमित संप्रभुता या रूस के क्षेत्रीय फ़ायदों को मान्यता देने के लिए मजबूर करने से इंटरनेशनल कानून का दिखावा नहीं बचेगा। रूस के हमले को नॉर्मल मानने से चीन-रूस गठबंधन को आज़ादी पर आधारित एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ावा मिलेगा। अगर रूस यूक्रेन में जीत जाता है, तो यह एक मिसाल कायम करेगा, जिससे दूसरी जगहों पर भी हमले की लड़ाइयों को बढ़ावा मिलेगा और एंटी-वेस्टर्न एक्सिस के लिए पूरे यूरोप में अपना असर बढ़ाने का रास्ता साफ़ होगा।

आज़ाद दुनिया का भविष्य इसे बचाने के हमारे सामूहिक इरादे पर टिका है। जबकि इंसानी इतिहास के इस अहम समय में अमेरिका की भूमिका निराशाजनक है, दुनिया में नियमों पर आधारित व्यवस्था के मुख्य एंकर के तौर पर यूरोपियन यूनियन पर एक खास ज़िम्मेदारी आती है। हमारा साझा लक्ष्य आक्रामक रूसी शासन को हराना और दुनिया की आज़ादी को खत्म करने की कोशिश करने वाली ताकतों को कमज़ोर करना होना चाहिए।

© एरियाना गिक, मार्को मिहकेल्सन और रोमन सोहन, 2025